नईदुनिया

फॉक्सकॉन भारत में दोगुनी नौकरी देगी: निवेश और बिजनेस भी बढ़ाएगी कंपनी, कहा- अगले साल जन्मदिन पर पीएम को देंगे बड़ा गिफ्ट

नई दिल्ली।
ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने भारत में अपने वर्कफोर्स और इन्वेस्टमेंट को दोगुना करने की योजना बनाई है। देश में कंपनी के रिप्रजेंटिव वी ली ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा, आपके नेतृत्व में भारत में फॉक्सकॉन तेजी से विकसित हुई है। हम भारत में रोजगार, बिजनेस के साइज को दोगुना करने का लक्ष्य रखते हुए, अगले साल आपको एक बड़ा जन्मदिन का उपहार देने के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे।

तमिलनाडु प्लांट में 40,000 लोगों को नौकरी देती है कंपनी - मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फॉक्सकॉन के तमिलनाडु प्लांट में अभी 40,000 लोग काम करते हैं। वहीं, पिछले साल रॉयटर्स ने बताया था कि अगले दो सालों में फॉक्सकॉन 53,000 लोगों को नौकरी में रखने की योजना बना रहा है।

भारत सरकार की पीएलआई स्कीम का हिस्सा फॉक्सकॉन - एपल के तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर (फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन) भारत सरकार की 41,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम का हिस्सा हैं। इस स्कीम के बाद ही भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। 2020 में भारत सरकार ने पीएलआई को लॉन्च किया था। इस स्कीम से बाहर के देशों की कंपनीज को मौका मिलता है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का फायदा उठा सकें, साथ ही उस पर इन्सेंटिव भी कमा सकें।

चीन से एपल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट की जा रही - अमेरिका-चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण चीन से एपल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट की जा रही है। जियो पॉलिटिकल टेंशन और कोरोना महामारी के बाद एपल समेत अन्य अमेरिकी टेक दिग्गज भी चीन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के विस्तार पर काम कर रहे हैं।

कांचीपुरम में मोबाइल कंपोनेंट प्लांट लगाएगी फॉक्सकॉन - फॉक्सकॉन तमिलनाडु में मोबाइल कंपोनेंट प्लांट लगाएगी। इसके लिए ताइवान की होन हई टेक्नोलॉजी ग्रुप (फॉक्सकॉन) ने राज्य सरकार के साथ दो महीने पहले एक लेटर ऑफ इंटेट साइन किया है। इस प्लांट को कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंबुदूर में फॉक्सकॉन की मौजूदा आईफोन प्लांट के पास ही 1,600 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

इस हफ्ते तीन आईपीओ ओपन होंगेः सिग्नेचर ग्लोबल, साई सिल्क्स और वैभव जेम्स में निवेश का मौका, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,630

मुंबई। इस हफ्ते शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए तीन इनिशियल पब्लिक ऑफर ओपन होंगे। इसमें सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड, साई सिल्क्स (कलामंदिर) लिमिटेड और वैभव जेम्स एंड ज्वैलर्स लिमिटेड शामिल है। आइए इन तीनों कंपनियों के आईपीओ के बारे में एक-एक करके जानते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड इस आईपीओ के जरिए 730 करोड़ जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 20 सितंबर से 22 सितंबर तक अप्लाय कर सकते हैं। 4 अक्टूबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। कंपनी ने इस इश्यू का प्राइस बैंड 366-385 तय किया है। रिटेल निवेशकों मिनिमम एक लॉट यानी 38 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइज बैंड 385 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए 14,630 इन्वेस्ट करने होंगे। सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के आईपीओ के लिए रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 494 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपर प्राइज बैंड के हिसाब से 190,190 खर्च करने होंगे। साई सिल्क्स (कलामंदिर) लिमिटेड इस आईपीओ के जरिए 1,201 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 600 के फ्रेश शेयर इश्यू करेगी। वहीं, 601 करोड़ के शेयर कंपनी के मौजूदा निवेशक और प्रमोटर्स के जरिए बेचेंगे। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 20 सितंबर से 22 सितंबर तक अप्लाय कर सकते हैं। 4 अक्टूबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। कंपनी ने इस इश्यू का प्राइस बैंड 210-222 तय किया है। रिटेल निवेशकों मिनिमम एक लॉट यानी 67 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइज बैंड 222 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए 14,874 इन्वेस्ट करने होंगे। साई सिल्क्स (कलामंदिर) लिमिटेड के आईपीओ के लिए रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 871 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपर प्राइज बैंड के हिसाब से 193,362 खर्च करने होंगे। वैभव जेम्स एंड ज्वैलर्स लिमिटेड इस आईपीओ के जरिए 270.20 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 210 के फ्रेश शेयर इश्यू करेगी। वहीं, 60.20 करोड़ के शेयर कंपनी के मौजूदा निवेशक और प्रमोटर्स के जरिए बेचेंगे। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 22 सितंबर से 26 सितंबर तक अप्लाय कर सकते हैं। 6 अक्टूबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। वैभव जेम्स एंड ज्वैलर्स लिमिटेड ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 204-215 तय किया है। रिटेल निवेशकों मिनिमम एक लॉट यानी 69 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइज बैंड 215 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए 14,835 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, रिटेल निवेशक मैक्सिमम इस आईपीओ के लिए 13 लॉट यानी 897 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपर प्राइज बैंड के हिसाब से 192,855 खर्च करने होंगे।

अब चॉकलेट भेजकर किस्त चुकाने के लिए याद दिलाएगा एसबीआई, डिफॉल्टर्स के लिए बैंक ने बनाई यह योजना

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने खुदरा कर्ज लेने वालों को समय पर लोन की किस्त चुकाने की याद दिलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। किस्त से चूकने वालों की जिन ग्राहकों की संभावना दिख रही है, उनको बैंक चॉकलेट का एक पैकेट भेज रहा है। बैंक ने कहा, जो कर्जदार डिफॉल्ट करने की योजना बना रहा है, वह बैंक के बार-बार कॉल का जवाब नहीं देगा। इसलिए अच्छा तरीका है कि आप बिना बताए उनसे उनके घर पर मिलें। बैंक ने कहा, यह कदम बेहतर कलेक्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिस्टम में खुदरा कर्ज के बढ़ते स्तर के साथ-साथ ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच उठाया गया है। जून, 2023 की तिमाही में एसबीआई का कुल खुदरा कर्ज 16.46 फीसदी से अधिक बढ़कर 12.04 लाख करोड़ रहा है। बैंक का कुल कर्ज 13.9 फीसदी बढ़कर 33.03 लाख करोड़ रुपये रहा है। एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेस का इस्तेमाल करने वाली दो फिनटेक कंपनियों के साथ हम अपने खुदरा ग्राहकों को किस्त याद दिलाने का एक नया तरीका अपना रहे हैं, जिन ग्राहकों की किस्त चूकने की आशंका है, उनसे फिनटेक प्रतिनिधि मिलने जाएंगे।

अडाणी-हिंडनबर्ग केस जांच के लिए नई कमेटी बनाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में कहा कमेटी में बेदाग छवि वाले लोग शामिल हों

नई दिल्ली।
अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में नई एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का अनुरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि कमेटी में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाए, जिनकी छवि बेदाग हो और जिनका अडाणी-हिंडनबर्ग मामले से किसी भी तरह से कोई लेना-देना न हो यानी हितों का टकराव न हो। याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने अपने वकील रमेश कुमार मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है। 24 जनवरी को अमेरिका की शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी।

6 सदस्यीय कमेटी के हेड सप्रे थे - कमेटी के हेड रिटायर्ड जज एएम सप्रे थे। उनके साथ कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट, एमवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन को भी शामिल किया गया था। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट 19 मई 2023 को सार्वजनिक की थी। कमेटी ने कहा था कि अडाणी के शेयरों की कीमत में कथित हेरफेर के पीछे सेबी की नाकामी थी, अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कमेटी ने रिपोर्ट में कहा- सेबी को संदेह है कि अडाणी ग्रुप में निवेश करने वाले 13 विदेशी फंडों के प्रमोटर्स के साथ संबंध हो सकते हैं। अडाणी ग्रुप के शेयरों में वॉश ट्रेड का कोई भी पैटर्न नहीं मिला है। वॉश ट्रेड यानी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए खुद ही शेयर खरीदना और बेचना। कुछ संस्थाओं ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले शॉर्ट पोजीशन ली थी। जब शेयर के भाव गिरे तो इसे खरीदकर मुनाफा कमाया।

ओपी भट, केवी कामथ और सोमशेखर सुंदरेसन पर सवाल - नई याचिका में एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट, केवी कामथ और सोमशेखर सुंदरेसन के शामिल होने पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि इन मेंबर्स के समिति में

शामिल होने से हितों का टकराव हो रहा है। ओपी भट रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी ग्रीनको के चेयरमैन हैं। भारत में अडाणी की फैसिलिटीज को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्रीनको और अडाणी ग्रुप मार्च 2022 से क्लोज पार्टनरशिप में हैं। आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित सीबीआई की एफआईआर में केवी कामथ का नाम है। केवी कामथ 1996 से 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन थे। यह मामला बैंक की एमडी रहीं चंदा कोचर से जुड़ा है।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ:

सबसे पहले चार जनहित याचिका दायर की - मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और एफआईआर की मांग की थी। इसके साथ ही इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक की भी मांग की गई थी। विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की थी। तिवारी ने अपनी याचिका में लोगों के उन हालातों के बारे में बताया था जब शेयर प्राइस नीचे गिर जाते हैं। जया ठाकुर ने इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका पर संदेह जताया था। उन्होंने एलआईसी और एसबीआई की अडाणी एंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की भूमिका की जांच की मांग की थी। मुकेश कुमार ने अपनी याचिका में आयकर विभाग, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच के निर्देश देने की मांग की थी। मुकेश कुमार ने अपने वकीलों रूपेश सिंह भदौरिया और महेश प्रवीर सहाय के जरिए ये याचिका दाखिल कराई थी।

कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को बनाई 6 सदस्यीय कमेटी - सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कमेटी बनाई थी, उसके हेड रिटायर्ड जज एएम सप्रे हैं। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट, एमवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कमेटी बनाने का यह आदेश 2 मार्च को दिया था। 19 मई को कमेटी ने रिपोर्ट सार्वजनिक की थी।

सेबी को इन 2 पहलुओं पर जांच करने के लिए कहा - क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के नियम 19 का उल्लंघन हुआ क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़ा है नियम 19 कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स का नियम 19 शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग से जुड़ा है। भारतीय कानून में किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग पब्लिक यानी नॉन इनसाइडर्स की होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी विदेश में शेल कंपनियों को मैनेज करते हैं। इनके जरिए भारत में अडाणी ग्रुप की लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर ट्रांसफर किए गए। इसने अडाणी ग्रुप को कानूनों से बचने में मदद की।

सेबी को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मिला - सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया। कोर्ट ने इससे पहले 2 मार्च को सेबी को जांच के लिए 2 महीने का समय दिया था। यानी उसे 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि, सेबी ने कहा था कि अडाणी ग्रुप के ट्रांजैक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जांच के लिए उसे कम से कम 6 महीने का अतिरिक्त समय चाहिए।

वोडाफोन-आइडिया ने सरकार को 1701 करोड़ का इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया

2022 में खरीदा था 5जी स्पेक्ट्रम, कंपनी पर 2.1 लाख करोड़ का कर्ज

नई दिल्ली।
टेलिकॉम ऑपरेटर वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड ने सरकार को 5जी और कुछ अन्य स्पेक्ट्रम के लिए 1,701 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। कंपनी ने इन स्पेक्ट्रम को पिछले साल खरीदा था। लेकिन करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए की कर्ज में डूबी कंपनी ने इसके पेमेंट में देरी कर दी थी, जिसके चलते उसे कुछ अतिरिक्त पेमेंट भी करनी पड़ी है। सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि वोडाफोन-आइडिया की ओर से स्पेक्ट्रम के इंस्टॉलमेंट के तौर पर 1,701 करोड़ का चेक मिला है। कंपनी फिलहाल, सब्सक्राइबर्स की कमी के चलते फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड में सरकार का 33 प्रतिशत स्टेक है। जिसे सरकार ने कुछ फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट के बदले ले रखा है।

वीआई पर कमाई से ज्यादा लायबिलिटी

वोडाफोन-आइडिया का सालाना इंस्टॉलमेंट 16,000 करोड़ है। जबकि, उसकी मौजूदा (अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोरटाइजेशन) 10,000 करोड़ है।

टेलिकॉम ऑपरेटर के शेयरों में पिछले एक महीने में 51 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी रही है। कंपनी का स्टॉक 9.63 प्रतिशत बढ़कर 11.95 रुपए हो गया, जो एक साल में इसका उच्चतम स्तर है। वहीं सालाना स्तर पर कंपनी का शेयर 109.65 प्रतिशत बढ़ा है।

वोडाफोन-आइडिया के यूजर्स की संख्या गिरी

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार जून 2023 में कंपनी के यूजर्स की संख्या लगातार कम हुई थी। वोडाफोन-आइडिया के 12.85 लाख यूजर्स ने इस दौरान नेटवर्क को छोड़ा था। इससे कंपनी के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 22.97 करोड़ रह गई है। इससे पहले कंपनी ने मई 2023 में 28.2 लाख यूजर्स खोए थे।

मुंबई के डेवलपर के खिलाफ केस दर्ज, एसबीआई और अन्य 15 बैंकों से 38 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

नई दिल्ली।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और 15 बैंकों के साथ 3,800 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई स्थित यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (यूआईएल), उसके मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी), तीन निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एसबीआई की स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच के डिप्टी जनरल मैनेजर की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार, एसबीआई और अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों की ओर से यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को लगभग 3,800 करोड़ रुपये की क्रेडिट/ऋण सुविधाएं, फंड-आधारित और गैर-फंड आधारित मंजूर की गईं। प्राथमिकी में कहा गया है, उक्त कंपनी ने फर्जी एलसी ट्रेड मॉडल के माध्यम से किए गए फर्जी लेनदेन, डेटा में हेराफेरी करके अनुचित समायोजन प्रविष्टियों, गैर-कंसोर्टियम खातों के माध्यम से धन का विपथन, संबंधित पक्षों के माध्यम से धन का विचलन और अस्पष्ट रूप से अधिक भुगतान, एसबीआई और अन्य कंसोर्टियम बैंकों के धन का गबन किया और इस तरह इन बैंकों को धोखा दिया। एफआईआर में यूआईएल, उसके सीएमडी किशोर

अवरसेकर, वाइस चेयरमैन और प्रमोटर गारंटर अभिजीत आवरसेकर, कार्यकारी निदेशक आशीष अवारसेकर, पूर्णकालिक निदेशक प्रमोटर पुष्पा अवरसेकर, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के नाम हैं। इसमें कहा गया है कि प्रथम दृष्टया शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 420 तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 420 (1) (डी) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराधों का खुलासा होता है।

सोना और चांदी की कीमतों में तेजी, सोना 59 हजार पार, चांदी 72 हजार रुपए

नई दिल्ली।
इस सप्ताह चांदी के वायदा की शुरुआत तेजी के साथ हुई लेकिन सोने के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। हालांकि बाद में यह गिरावट थम गई और सोना का वायदा भाव तेजी के साथ कारोबार करने लगा। सोने के वायदा भाव अब 59 हजार रुपए से ऊपर और चांदी के वायदा भाव 72 हजार रुपए से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी के वायदा भाव में सुस्त शुरुआत के बाद तेजी देखी जाने लगी। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 68 रुपए की तेजी के साथ 72,222 रुपए के भाव पर खुला। फिलहाल यह कॉन्ट्रैक्ट 154 रुपए की तेजी के साथ 72,308 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसने 72,357 रुपए के भाव पर दिन का उच्च और 72,217 रुपए प्रति किलो के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। मई महीने में चांदी के वायदा भाव 78 हजार रुपए किलो को पार कर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए थे। सोने के वायदा भाव की शुरुआत भी आज नरमी के साथ हुई लेकिन बाद में बाद बढ़ने लगे। एमएसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 80 रुपए की गिरावट के साथ 58,913 रुपए के भाव पर खुला। हालांकि खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 118 रुपए की तेजी के साथ 59,111 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 59,185 रुपए के भाव पर दिन का उच्च स्तर और 58,913 रुपए के भाव पर निचला स्तर छू लिया। मई महीने में सोने के वायदा भाव ने 61,845 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले लेकिन बाद में इनके भाव भी चढने लगे। कॉमेक्स पर सोना 1945.70 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद प्राइस 1946.20 डॉलर था। फिलहाल यह 4 डॉलर की तेजी के साथ 1950.20 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 23.32 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद प्राइस 23.38 डॉलर था। फिलहाल यह 0.02 डॉलर की तेजी के साथ 23.41 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रही थी।

ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंसः देश में पेट्रोलियम पदार्थों के बाजार पर यह क्या असर डालेगा

नई दिल्ली।
बीते 9 सितंबर को भारत ने जी 20 के दौरान एक बड़ी घोषणा की- एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के गठन का एलान किया गया। भारत, अमेरिका और ब्राजील इसके संस्थापक सदस्य होंगे। 19 अन्य देश भी समर्थन देने के लिए इसमें शामिल होंगे। अब इससे पहले कि हम इस बात पर जाएं कि पृथ्वी पर हमें ऐसे गठबंधन की आवश्यकता क्यों है, हमें जैव ईंधन को समझने की जरुरत है। हम मुख्य रूप से इथेनॉल और बायोडीजल के बारे में बात कर रहे हैं।

इन्हें जैव ईंधन कहा जाता है क्योंकि उन्हें पौधों पर आधारित पदार्थों से निकाला जा सकता है। गन्ने से इथेनॉल निकाला जा सकता है। आप इसे मकई, चावल और बांस की विभिन्न प्रजातियों से निकाल सकते हैं। दूसरी ओर बायोडीजल पशु वसा, वनस्पति तेल, सोयाबीन तेल और यहां तक कि रेस्तरां ग्रीस से बनाया जा सकता है। इन्हें आम तौर पर फेंक दिया जाता है उसे वास्तव में किसी ऐसी चीज में संसाधित किया जा सकता है जो वास्तव में उपयोगी है। कुछ उद्यमी लोग शैवाल द्वारा स्रावित तेलों को भी बायोडीजन में परिवर्तित कर रहे हैं।

भारत में इन दिनों जैव ईंधन की बड़ी चर्चा है। हम मध्य पूर्व और अन्य जगहों से महंगे दामों पर

बैरल के बैरल तेल आयात करने पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। हम अच्छे तेल रिफाइनर हैं, लेकिन बड़े उत्पादक नहीं हैं, इसलिए, हमें इस काले सोने के विकल्प की आवश्यकता है। हमारे पास आसानी से दोहन करने के लिए तेल का विशाल भंडार नहीं है।

इथेनॉल और बायोडीजल का इस्तेमाल कर हमने आयात मद में 73 हजार करोड़ बचाए - वहीं दूसरी ओर जैव ईंधन में किसी तरह का पेट्रोलियम पदार्थ शामिल नहीं है। पिछले 9 वर्षों में, भारत ने स्पष्ट रूप से घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल और बायोडीजल पर भरोसा करके आयात मद में 73,000 करोड़ रुपये की बचत की है। हम पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण कर रहे हैं। जब आप ईंधन पंप तेल लेने के लिए जाते हैं तो आपकी कार को तेल का हाइब्रिड मिश्रण मिल रहा है। दूसरी ओर, हम पारंपरिक डीजल के साथ बायोडीजल का भी मिश्रण कर रहे हैं।

ऐसे में हम यह देख सकते हैं कि जैव ईंधन हमारे भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से कीमती डॉलर को बचाया जा सकता है जो हम पेट्रोल-डीजल के आयात के नाम पर फूंक रहे हैं। यह देश को कुछ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर बना सकता है। आखिरकार यह देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे पास जैव ईंधन (2018) पर एक समर्पित राष्ट्रीय नीति है। इस नीति में 2022 में एक संशोधन भी किया गया। इस समय चीजें काफी अच्छी चल रही हैं। हमने शुरू में 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अभी, लक्ष्य को 2026 तक संशोधित किया गया है। हम अधिक आश्वस्त हैं। हमने 2030 तक पारंपरिक डीजल में 5 प्रतिशत बायोडीजल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। अब एक पहलू निश्चित रूप से आयात को कम करके पैसे बचा रहा है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि जैव ईंधन प्रदूषण में उतना योगदान नहीं देते हैं। देखिए, देश का 40 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है। कम से कम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का तो यही कहना है। वहीं इथेनॉल अपेक्षाकृत सफाई से जलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को कम करता है।

जैव ईंधन के मामले में आगे बढ़ने के लिए एक गठबंधन की जरूरत क्यों - यह सब ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) की आवश्यकता क्यों है हम इसे अकेले क्यों नहीं कर सकते क्या इस मामले में होने वाला गठबंधन ओपेक की तरह है जहां पेट्रोलियम उत्पादक देश एक साथ बैठक करते हैं और यह तय करते हैं कि कितने जैव ईंधन की आपूर्ति करनी है या नहीं इसका जवाब तलाशना जरूरी है। बात यह है कि जैव ईंधन के मामले में भारत की कुछ बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। उदाहरण के लिए, हमने पहले उल्लेख किए गए मील के पत्थर को हासिल करने के लिए, 17 बिलियन लीटर इथेनॉल की आवश्यकता है। हम वर्तमान में केवल 10 बिलियन लीटर का उत्पादन करते हैं। फिलहाल, हम वास्तव में दुनिया के जैव ईंधन उत्पादन का सिर्फ 3 प्रतिशत हिस्सा ही तैयार करते हैं। इसके लिए दुनिया के ऐसे देशों बीच गठबंधन की जरूरत थी, जो हमारी ही तरह की उपलब्ध हासिल करना चाहते हैं। यही कारण है भारत, अमेरिका और ब्राजील जैसे देश जीबीए के लिए साथ आए हैं।

जीबीए से जैव ईंधन के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय निधियों तक पहुंचने में मिलेगी मदद - यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास देश में बायोगैस के लिए 5,000 संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है। हमें इसे पंप करने के लिए मदद की जरूरत है। एक गठबंधन होने से हमें मदद मिलेगी। इससे हमें न केवल तकनीकी जानकारी में सुधार करने में, बल्कि इसके लिए स्थापित विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय निधियों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के मामले में हुआ था - 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017